श्री उपसभापतिः आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। Please take your seat. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। बलूनी जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल बलूनीः महोदय, अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके में किसी से भी पूछा जाए कि दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन कौन सा है, तो वह मसूरी या नैनीताल का नाम लेगा। ...(**व्यवधान**)... महोदय, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन लैंसडाउन है। जो कि दिल्ली से केवल 270 किलोमीटर की दूरी पर है। महोदय, यह नैसर्गिक छटा से परिपूर्ण है। हिमालय का पूरा दृश्य वहां से दिखता है। ...(**व्यवधान**)... वहां पर जो बेस कैम्प है, ...(**व्यवधान**)... ऋषि कण्व आश्रम भी वहां पर है, वहां पर सिद्धबली की बहुत बड़ी पीठ है, वहां पर तारकेश्वर महादेव भी हैं। महोदय, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड होने का कारण लैंसडाउन के विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के आग्रह है कि अगर लैंसडाउन के कुछ हिस्से को डिनोटिफाई कर दिया जाए या कैंटोनमेंट बोर्ड के नियम में कुछ छूट दी जाए, तो निश्चित रूप से लैंसडाउन देश का लोकप्रिय और पर्यटकों का पसंदीदा टूरिस्ट स्थल बन सकता है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्रीमती सुलता देव। ...(**व्यवधान**)... यह ज़ीरो ऑवर है और ज़ीरो ऑवर में जिनके नाम सैंक्शंड हैं, वे ही बोलेंगे, और अन्य किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

Need for tackling underfunding and red-tapism in the implementation of schemes under the Nirbhaya Fund

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा)**:** सर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपना मत दे रही हूं, जो कि निर्भया फंड के संबंध में है। महोदय, निर्भया फंड के अंतर्गत आने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं कम फंडिंग और लालफीताशाही की समस्या से ग्रसित हैं, जिन पर न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ...(**व्यवधान**)... निर्भया फंड के तहत धन का कम उपयोग हुआ है। यह फंड केवल तीन परियोजनाओं और 7 राज्यों में केंद्रित हो गया है। जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। One Stop Centre के संबंध में धन का प्रभाव असंगत होता जा रहा है। इसके प्रभावी कार्यान्यवन में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मैं तो यह बोलती हूं कि जो फंड दिया जा रहा है ...(**व्यवधान**)... जैसे ये तीन परियाजनाओं और 7 स्टेट्स को कैरी कर रहा है, तो इसमें सारे देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को लाना चाहिए।

अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में 11,273 केसेज़ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। इसके साथ ही पैसे की कमी हो रही हैं, कम फंडिंग हो रही है, युटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। 'वन स्टॉप सैंटर' में जो कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए भी सैलरी का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, स्टाफ की शॉर्टेज है,

ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। महोदय, यह भी देखा जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। निर्भया फंड गुजरात में तो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर ओडिशा और बाकी पाँच राज्यों में इस फंड के फ्लो में इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूं कि यह एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जिन महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उन पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए, उन्हें एड्रेस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जितने केसेज़ लंबित हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा किया जाए। 'वन स्टॉप सैंटर' और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी केसेज़ का निबटारा किया जाए। इसके साथ ही इस फंड का भी अच्छी तरह से फ्लो हो। जो रेड टेपिज्म में बंद है, उसके लिए भी कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल की जरूरत होती है। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक अधिकारी विधि व्यवस्था में इस फंड को किस तरह से जल्दी से जल्दी स्टेट्स को दिया जाए, जिसके कारण सभी बेनिफिटेड हों। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इसे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटोरीज़ में लगाया जाए। उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है ,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, वंदे उत्कल जननी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

माननीय सदस्यगण, यह जीरो ऑवर है और नियमत: जीरो ऑवर में जिनके नाम लिस्टिड हैं, केवल वे सदस्य ही बोल सकते हैं।...(**व्यवधान**)... माननीय विजय पाल सिंह तोमर जी, आप 'Demand for increasing credit limit of kisan credit card from Rupees Three Lakhs to Five Lakhs' विषय पर अपनी बात रखिए।...(**व्यवधान**)... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

Demand to increase the credit limit of Kisan Credit Card from Rs. 3 Lakh to Rs. 5 Lakh

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं किसानों की एक बड़ी परेशानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर साहूकार के शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया था। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पशु पालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मैं इसके लिए सरकार तथा प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड से पूर्व किसानों को साहूकारों से 24 परसेंट और 36 परसेंट ब्याज पर ऋण मिलता था। उस पर चक्रवर्ती ब्याज देने के कारण बहुत से किसान अपनी भूमि से हाथ धो बैठते थे और इस तरह से साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण होता था। लेकिन अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से मात्र 3 लाख रुपये सालाना